>

Title: Need to allot adequate quota of houses under Indira Awaas Yojana to Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले देश के बी.पी.एल. परिवारों को जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है जिनकी पहचान पंचायत-वार सभी राज्यों ने विशेषकर मध्य प्रदेश ने करवाई है। उसी अनुसार इंदिरा आवास की मांग केन्द्र सरकार से लगातार की जा रही है । परंतु जो राज्य को इंदिरा आवास का कोटा दिया जा रहा है, वो अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत कम दिया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा आवास योजना सामान्य के लिए 3.38 लाख आवास, वनाधिकार पट्टाधिकारियों के लिए 1.60 लाख आवास एवं इंदिरा आवास होम स्टेड के लिए 105020 आवासों की मांग भारत सरकार से की गई है । किंतु वर्ष 2012-13 के लिए मध्य प्रदेश को 3490 अनुसूचित जाति, 5860 अनुसूचित जनजाति, 885 अल्पसंख्यक, 9405 सामान्य एवं 371 विकलांगों के लिए स्वीकृति दी गई है जो कि अत्यंत कम है जबकि कई राज्यों को जहां की आबादी कम है उन राज्यों को लाखों की संख्या में इंदिरा आवासों का आबंटन दिया गया है ।

मैं प्रदेश सरकार की मांग के अनुसार इंदिरा आवास के नए आबंटन दिए जाने की मांग करता हूं ।